ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

उदयपुर, शुक्रवार 31 जनवरी 2025

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

वर्ष 1 अंक 325

APK फाइल है खतरनाक, साइबर क्रिमिनल्स खुद डेवलप कर रहे ठगी का सॉफ्टवेयर!

24 न्यूज अपडेट

आज हर हाथ में स्मार्ट फोन है और फिंगरटिप्स पर रोजमर्रा के सारे काम हो रहे हैं. मोबाइल प्ले स्टोर में ऐसे कई ऐप्स की भरमार है, जिससे हम ऑनलाइन पेमेंट से लेकर बिलिंग तक का काम एक क्लिक में करना चाहते हैं. इसके साथ ही कई सरकारी स्कीम्स भी ऐप के रूप में लाए गए हैं. ऐसे में लोग इन ऐप्स को डाउनलोड करते हैं लेकिन इनको डाउनलोड करते समय अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बाद पछताना पड़ सकता है. क्योंकि आज ये साइबर ठगी का एक बड़ा जरिया बन गया है. झारखंड के जामताड़ा जिला के साइबर अपराधियों को देश भर में सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल्स माना जाता है. जामताड़ा कल भी खतरनाक था और आज भी खतरनाक है. क्योंकि अब ये अपराधी हाईटेक हो गये हैं और खुद का ऐप बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं. जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने खुद का ऐप बनाना सीख लिया है. जांच में यह बात सामने आई है कि जामताड़ा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जरिये ऐप बनाने की विधि सीख ली है. अब वे उसी ऐप के जरिए ठगी कर रहे हैं.

जामताड़ा मॉड्यूल हुआ पहले से ज्यादा खतरनाक

झारखंड में नक्सल से बड़ी समस्या के रूप में अब साइबर अपराधी सामने आ रहे है. साइबर अपराध की लिए देश भर में बदनाम जामताड़ा अब और कुख्यात हो गया है. जामताड़ा के साइबर अब फर्जी ऐप तैयार करना सीख गए हैं. यहां तक की फर्जी ऐप मोबाइल या लैपटॉप के एंटी वायरस की पकड़ में न आए, इसका तोड़ भी साइबर अपराधियों ने निकाल लिया है.

जामताड़ा के साइबर अपराधियों का एक समूह जिसका नाम डीके बॉस था, उसके जरिये साइबर अपराधियों ने 11 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर डाली थी. जब ठगी में शामिल साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई तो उसमें कई चौकाने वाले खुलासे हुए. राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जामताड़ा के इस नए मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की आई4सी और झारखंड सीआईडी एक साथ काम कर रही है. साथ ही झारखंड पुलिस ने आमलोगों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं.

प्ले स्टोर सेफ, APK खतरनाक

झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज (APK) बेहद खतरनाक है. अगर ठगी से बचना है तो गुगल प्ले स्टोर से ही किसी भी ऐप को डाउनलोड करें. क्योंकि अब एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज (APK) को खुद साइबर क्रिमिनल्स भी बनाकर उसे इंटरनेट पर डाल रहे हैं. आमलोगों को एकदम यह समझ लेना है कि एंड्राइड एप्लीकेशन पैकेज किसी भी कीमत पर डाउनलोड न करें.

आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, एक साथ 7 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा

24 न्यूज अपडेट

दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इन सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और AAP में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताई। महरौली से 2 बार के पार्टी विधायक नरेश यादव ने कहा, 'AAP का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था। लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूं कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि AAP ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है।' उधर, विधायकों के पार्टी से इस्तीफे पर AAP विधायक ऋतुराज झा ने भाजपा पर विधायकों को लालच देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'मुझे भी पार्टी छोड़ने का लालच दिया गया था। लेकिन मैं आखिरी दम तक AAP में रहूंगा।' AAP ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे। इस बार 26 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होना है। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा।

10 दिसंबर को सीलमपुर विधायक ने दिया था इस्तीफा

आम आदमी पार्टी ने 21 नवंबर को कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान का नाम नहीं था। इस पर अब्दुल रहमान खुलकर अरविंद केजरीवाल के विरोध में आ गए थे। 10 दिसंबर को अब्दुल रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर मुस्लिमों के प्रति बेरुखी का आरोप लगाया था।

विधायकों ने ये बताई इस्तीफे की वजह

1. नरेश यादव, महरौलीः सीट से विधायक रहे यादव ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि AAP ने भ्रष्टाचारियों को ही पार्टी में शामिल कर लिया है।
2. पवन शर्मा, आदर्श नगरः आम आदमी पार्टी जिस विचारधारा पर बनी थी, उस विचारधारा से भटक चुकी है। AAP की दुर्दशा देख कर मन बहुत दुखी है।
3. भूपेंदर सिंह जून, बिजवासनः आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापन जिन मूल्यों पर की गई थी, अब उन नैतिक मानदंडों की घोर उपेक्षा चिंताजनक है। पार्टी ने आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को टिकट दिया।
4. मदनलाल, कस्तूरबा नगरः मेरा आम आदमी पार्टी से भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं।
5. रोहित मेहरौलिया, त्रिलोकपुरीः जिन्हें बाबासाहब अंबेडकर की केवल फोटो चाहिए, उनके विचार नहीं, ऐसे मौका-परस्त और बनावटी लोगों से आज से मेरा नाता खत्म। मैं AAP की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से इस्तीफा देता हूं।
6. राजेश ऋषि, जनकपुरीः AAP भ्रष्टाचार मुक्त शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित थी। पार्टी से मैंने इन मूल्यों से एक महत्वपूर्ण दूरी देखी है। पार्टी करप्शन और भाई-भतीजावाद का कटोरा बन गई है।
7. भावना गौड़, पालमः मेरा पार्टी से विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसलिए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं।

जयललिता के आभूषण ले जाने के लिए 6 बड़े बक्से लेकर आएं, कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया

24 न्यूज अपडेट

बेंगलुरुः केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय मामलों के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश एच.ए. मोहन ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों को 14 और 15 फरवरी को अदालत में उपस्थित रहने और विशेष अदालत के पास मौजूद कीमती सामान को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया है. विशेष अदालत ने जुलाई 2023 में दिवंगत मुख्यमंत्री के कानूनी उत्तराधिकारी जे. दीपा और जे. दीपक की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जब्त संपत्तियों पर अधिकार का दावा किया था. फरवरी 2024 में विशेष अदालत ने कीमती सामान तमिलनाडु को सौंपने के लिए उसी साल मार्च में तारीखें तय की थीं. इसके बाद, दीपक और दीपा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी याचिकाओं पर निर्णय होने तक कीमती सामान सौंपने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. उच्च न्यायालय ने 13 जनवरी को जयललिता के आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त कीमती सामान पर अधिकार का दावा करने वाले कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था. क्या-क्या सामान हैः जयललिता के पास से 7,040 ग्राम वजन के 468 प्रकार के सोने और हीरे के आभूषण, 700 किलोग्राम चांदी के आभूषण, 740 महंगी चप्पलें, 11,344 रेशमी साड़ियां, 250 शॉल, 12 रेफ्रिजरेटर, 10 टीवी सेट, 8 वीसीआर, 1 वीडियो कैमरा, 4 सीडी प्लेयर, 2 ऑडियो डेक, 24 टू-इन-वन टेप रिकॉर्डर, 1040 वीडियो कैसेट, 3 लोहे के लॉकर, 1,93,202 रुपए नकद और कई अन्य सामान जब्त किए गए.

रामेश्वरम के पम्बन ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ देश का पहला वर्टिकल लिफ्टअप ब्रिज, 2 किमी लंबा; नीचे से कोस्ट गार्ड की बोट निकली

24 न्यूज अपडेट

तमिलनाडु के रामेश्वरम में बने नए पम्बन रेलवे ब्रिज पर शुक्रवार को रामेश्वरम एक्सप्रेस ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। ट्रेन को मंडपम से रामेश्वरम रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। इसमें कोई यात्री नहीं था। 2 साल बाद ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने से स्थानीय लोगों में खुशी है।

इसके अलावा वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज को पहली बार इंडियन कोस्ट गार्ड की पेट्रोलिंग बोट के लिए ऊपर उठाया गया। इसके बाद बोट ब्रिज के नीचे से गुजरी।

पम्बन ब्रिज इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। ये ब्रिज 2 किमी लंबा है, जो बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसे मौजूदा पम्बन ब्रिज के समानांतर बनाया गया है। इसमें समुद्र के पार 100 स्पैन हैं, जिनमें से 99 स्पैन 18-3 मीटर और एक स्पैन 72-5 मीटर माप का है।

पम्बन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज है, जो 531 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। ये ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि से जोड़ता है।

पहले 2 ट्रायल रन हुए

दक्षिण रेलवे ने 12 जुलाई, 2024 को नए पम्बन ब्रिज पर लाइट इंजन ट्रायल रन किया था, जिसमें पुल की संरचनात्मक अखंडता और विश्वसनीयता की पुष्टि की गई।

4 अगस्त, 2024 को आयोजित टावर कार ट्रायल रन के साथ, ब्रिज के पार रामेश्वरम स्टेशन तक एक ओएचई (ओवरहेड उपकरण) टावर कार का संचालन किया गया।

हमास ने माना- मिलिट्री चीफ दाइफ मारा गया पिछले साल जुलाई में इजराइल के हवाई हमले में मौत हुई थी; 5 दूसरे कमांडर भी मारे गए

24 न्यूज अपडेट

हमास ने गुरुवार को मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ की इजराइल के हवाई हमले में मौत की पुष्टि की। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक वीडियो जारी किया।

इस वीडियो में अबू ने दाइफ के अलावा हमास के डिप्टी कमांडर अबू तमा'आ, कॉम्बैट सपोर्ट चीफ रायद थाबेत और मिलिट्री विंग के चीफ ऑफ स्टाफ रफा सलामेह, खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर अयमान नोफाल, सेंट्रल और नॉर्थ गाजा ब्रिगेड के कमांडर अहमद गंदूर की मौत की जानकारी भी दी।

इजराइल के मुताबिक दाइफ की पिछले साल 23 जुलाई को हवाई हमले में मौत हो गई थी। इजराइल ने खान यूनुस में ब्रिगेड कमांडर रफा सलामेह के ठिकाने पर हमले किया था, जहां दाइफ भी मौजूद था।

सोने न दे सोना : फिर नया रिकॉर्ड, सोना लेकसिटी में @ 84000

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार स्थानीय भाव इस प्रकार रहे। चांदी टंच प्रति किलोग्राम 93850, चांदी चौरसा 93200, सोना स्टैंडर्ड (999) 84000, सोना जेवराती (23 कैरेट) 80640, सोना (22 कैरेट) 77280 रुपए। एसोसिएशन के इंदरसिंह मेहता ने बताया कि लेकसिटी में आज फिर गोल्ड में नया रिकॉर्ड बना। उदयपुर में सोना लगातार हर रोज़ भाव का उच्चतम नया नया रिकार्ड बन रहा है। आम बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी आज (31 जनवरी) सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।

4 महानगरों और भोपाल में सोने की कीमत

दिल्ली : 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,450 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 84,480 रुपए है।

मुंबई : 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 84,330 रुपए है।

कोलकाता : 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 77,300 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 84,330 रुपए है।

चेन्नई : 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,300 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 84,330 रुपए है।

भोपाल : 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 77,350 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 84,380 रुपए है।

सोने में तेजी के 5 प्रमुख कारण

ट्रम्प के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से जियोलॉजिकल टेंशन बढ़ गई हैं।
अमेरिका ने हाल ही में ब्याज दरों में कटौती की है, आगे भी कटौती कर सकता है।

डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से सोना महंगा हो रहा है।
महंगाई बढ़ने से भी सोने की कीमत को सपोर्ट मिल रहा है ।
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने से लोग गोल्ड में निवेश बढ़ा रहे हैं।

संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेशःअप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही; GDP ग्रोथ 6.3% से 6.8% रह सकती है

24 न्यूज अपडेट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके अनुसार FY26 यानी, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान GDP ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं रिटेल महंगाई अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें देश की GDP का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां होती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसे तैयार करता है।

इकोनॉमिक सर्वे 2025 की 6 बड़ी बातेंः

2025-2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगले एक से दो दशक तक 8% के दर से आर्थिक विकास करना होगा।

2023-2024 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई। चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद है। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने-पीने की महंगाई बढ़ी। सर्वे में कहा गया है कि लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए है। FY24 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आई। वहीं EPFO में नेट पेरोल पिछले 6 साल में दोगुना हुआ जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का अच्छा संकेत है। एआई का तेजी से हो रहा विकास न केवल ग्लोबल लेबर मार्केट में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है। AI के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की जरूरत है। भारत को अगले 20 साल में तेज ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की जरूरत है। पिछले 5 साल में सरकार ने फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। पब्लिक फंडिंग से अकेले ये जरूरतें पूरी नहीं होंगी, इसलिए प्राइवेट भागीदारी बढ़ानी होगी। भारतीय बाज़ारों के सामने सबसे बड़ा जोखिम अमेरिका से जुड़ा है। सर्वे में अमेरिकी बाजार में करेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी बताई गई है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर असर पड़ सकता है, खासकर रिटेल निवेशकों पर।

संपादकीय : चुनावी सरोकार

अगर राजनीतिक दल स्वच्छ पेयजल को चुनाव का मुद्दा बनाते हैं तो यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि यह सभी लोगों की सेहत और जीवन से जुड़ा मामला है। लेकिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह एक बार फिर यमुना के पानी के प्रदूषित होने और इससे लोगों के सामने पैदा खतरे का मुद्दा और उस पर विवाद उठा है, वह नई बात नहीं है। गौरतलब है कि यमुना दिल्ली में हरियाणा से होकर आती है और दिल्ली में पीने के पानी का एक बड़ा स्रोत है। कुछ दिन पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। इसके अलावा, दिल्ली में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में स्वाभाविक ही यह आरोप एक विवाद का विषय बन गया और चुनाव आयोग ने भी इस मसले पर अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा। जाहिर है दिल्ली के बाशिंदों के लिए जिन अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी, वहां अब फिलहाल बहस इस बात पर है इस मामले में कौन पक्ष सच बोल रहा है! दिल्ली में फिलहाल आम आदमी पार्टी और केंद्र में भाजपा की सरकार है। देश की राजधानी होने के नाते उम्मीद की जाती है कि यहां कम से कम बुनियादी जरूरतों के मसले पर सरकारी तंत्र इतना सजग होगा कि स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कोई समस्या नहीं बनेगी। मगर यह छिपा नहीं है कि अक्सर किसी न किसी इलाके से प्रदूषित पानी की आपूर्ति की शिकायतें आती रहती हैं। कई बार पानी की गुणवत्ता इस स्तर की पाई जाती है कि उसे पीना सेहत के लिए खतरनाक होता है। आए दिन पानी की कमी जैसी चिंता भी जाहिर की जाती रहती है। दूषित पेयजल की शिकायत सामने आने के बाद शायद ही कभी इस समस्या के लिए किसी की जिम्मेदारी तय की जाती है। कोई तात्कालिक उपाय करने के बजाय इसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश नहीं होती। मगर चुनाव नजदीक आने के साथ ही सभी राजनीतिक दल यमुना के पानी के प्रदूषित होने, इसकी वजह से पेयजल की स्वच्छता प्रभावित होने और उसके जोखिम को मुद्दा बनाने लगते हैं। विडंबना यह है कि जैसे ही चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सरकार बन जाती है, तब सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। यमुना का पानी दूषित होने के कारण जगजाहिर रहे हैं जो पार्टियों चुनाव प्रचार के दौरान यमुना की सफाई और उसे एक स्वच्छ नदी बनाने के वादे करती हैं, बाद में उनके लिए यह सवाल गौण हो जाता है। सरकार इस नदी की सफाई के लिए आए दिन अपना सरोकार जताती है, उस पर धन खर्च किया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि बीते कई दशक से यमुना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन कर रह जाती है और बाकी समय दिल्ली के लोग आमतौर पर पीने के साफ पानी को लेकर हर वक्त एक आशंका से गुजरते रहते हैं। जिन राज्यों से यमुना गुजरती है, उनके अपने तर्क हैं। मगर किसी के लिए यह सवाल महत्त्वपूर्ण नहीं है कि इतने लंबे वक्त और अरबों खर्च किए जाने के बावजूद यमुना अमोनिया का स्तर चिंताजनक क्यों हो जाता है, इसका पानी नहाने तक के लिए सुरक्षित क्यों नहीं बन सका। आज भी अगर यमुना सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ही बनी हुई है तो इस मसले पर जताई जाने वाली चिंताओं के प्रति राजनीतिक पार्टियों की इच्छाशक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है।

मुनाफे का सफर

विमानन कंपनियों के विस्तार और रस्ते हवाई टिकट के वादे के बाद उम्मीद जगी थी कि कम आय वर्ग से आने वाला आम आदमी भी जरूरत पड़ने पर विमान यात्रा कर सकेगा। रेलगाड़ियों में असुविधाओं, टिकट के दाम और उनकी उपलब्धता की स्थिति में उसे एक विकल्प मिलेगा। मगर प्रीमियम किराए का दौर शुरू होते ही और मांग तथा पूर्ति में असंतुलन की आड़ में मनमानी होने लगी। आसमान छूते विमान किराए ने आम आदमी को फिर से जमीन पर उतार दिया। अब एक बार फिर हवाई सफर ज्यादा समर्थ लोगों की ही पहुंच में सिमटता जा रहा है। प्रमुख त्योहारों के समय, शादियों के मौसम में या छुट्टियों के दौरान कहीं जाने वालों से मुनाफाखोरी होने पर भी नागर विमानन मंत्रालय आंखें मूंदे रहता है। नतीजा यह कि यात्रियों के हितों को नजरअंदाज करते हुए ज्यादातर कंपनियां अंतिम समय में बेहिसाब किराया वसूल रही देती हैं। जबकि कई बार कुछ लोग आपात स्थिति और मजबूरी में भी आखिर में विमान यात्रा का विकल्प चुनते हैं। हैरत है कि सरकार न तो हस्तक्षेप करती है। और न ही कोई दिशा-निर्देश जारी करती है। जाहिर है, विमानन कंपनियों के इस तरह मुनाफा पर कोई लगाम नहीं है। कुंभ के दौरान जिस तरह से किराए में भारी उछाल आया है, उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देर से ही सही, सरकार हरकत में आई है। उसके निर्देश के बाद एक विमानन कंपनी 'इंडिगो' ने अपने किराए में तीस से पचास फीसद तक कटौती कर दी। इससे यही लगता है कि किराया वसूलने के मामले में विमानन कंपनियां किस तरह की मनमानी करती हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति की बैठक में आसमान छूते हवाई किराए पर गहरी चिंता जताई गई थी। मांग आधारित किराए की व्यवस्था में जब तीन-चार हजार का टिकट अठारह या बीस हजार का हो जाए, तो हवाई सफर सपना ही बने लगता है। मांग बढ़ने पर या अंतिम समय में टिकट चाहने वालों से मनमाना किराया वसूलने के पीछे आखिर क्या आधार होते हैं ? सरकार भी विमान किराए में पारदर्शिता लाने, मनमानी और मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में विफल रही है। सवाल है कि जिन आधारों पर किराए बढ़ाए जाते हैं, उन्हें तर्कसंगत क्यों नहीं बनाया जाता !

अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था....मिड डे मिल के टेण्डर में सरकारी मेहरबानी, 55 रूपए के काम का टेण्डर दे दिया 14 रूपए 49 पैसे में ??

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट, डूंगरपुर। इस टेण्डर पर यह पंक्तियां चरितार्थ हो रही है-अपनों ने हमें लूटा, गैरों में कहां दम था, अपनी तो कश्ती भी वहीं पर डूबी जहां पानी कम था। मामला डूंगरपुर में हाल ही दिए गए एक टेण्डर के वर्कऑर्डर का है जो मिड डे मील वितरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मिड डे मील याने कि एमडीएम के इस टेण्डर में जहां देखो वहां पर झोल दिखाई देते हैं। सरकारी सिस्टम किस तरह से किसी एक के लाभ के लिए सभी हदें पार कर जाता है, इसका ही उदाहरण है। इस टेण्डर में हुआ ये है कि अब तक जो सरकारी सिस्टम डूंगरपुर जिले में मिड डे मिल को स्कूलों तक पहुंचाने का काम कर रहा था वह कुल 55 रूपए का खर्च करके यह काम कर रहा था। इसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी मुश्किल से निकल रही थी। जगह-जगह बड़े बड़े गोदामों का मेंटेनेंस हो रहा था। अब वही काम नेताओं और सरकार की मेहरबानी से एक फर्म को 14 रूपए 49 पैसे में दे दिया गया है। साधारण सा गणित समझें तो यह लगभग असंभव है। यदि होगा तो इसमें भ्रष्टाचार जैसा कुछ नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसके साथ ही सहकारी समिति जो यह काम कर रही थी, उसको निजी कंपनी को बाईपास करने से कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे व करोड़ों के गोदामों पर ताले लग जाएंगे जो जनता के सरकारी पैसों से बने हैं।

यह है मामला

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक स्कूलों में मिड डे मील का जिम्मा दिया जा रहा था। इसके लिए पूरे जिले में गोदाम भी बने हुए हैं। इस व्यवस्था में सरकारी कर्मचारी भी जुड़े हैं तो समिति सदस्यों के रूप में अन्य भी। मिली जुली व्यवस्था से निगरानी भी पक्की हो रही थी। सितंबर में जब नया टेण्डर निकाला गया तो सात फर्मों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें से एक पार्टी की बिड तकनीकी रूप से सफल मिली तो एक ही पार्टी होने का तर्क देते हुए निरस्त कर दिया गया। दूसरी बार टेण्डर दिसंबर हुआ व फिर से सात पार्टियों ने टेण्डर डाले व इस बार भी एक के नाम पर खुला। टेण्डर फर्म निवेदिता को जनवरी के अंतिम सप्ताह में वर्कऑर्डर जारी किया गया।

यह है पैसों का गणित

सरकारी दर से यह काम कराने में संस्था को 15 प्रति क्विंटल आय से संस्था कार्मिकों का वेतन निकलता है। इस कार्य के लिए वास्तविक व्यय मजदूरी एफसीआई से संस्था गोदाम तक पहुंचाने का 7 रूपया क्विंटल एवं एफसीआई से संस्था तक गोदाम किराया 8 रूपया, संस्था गोदाम से स्कूल तक मजदूरी 7 रूपए तथा संस्था गोदाम से स्कूल तक किराया पीडीएस की दर के अनुसार 33 रूपए वास्तविक है। याने कि कुल 55 प्रति क्विंटल व्यय हो रहा है। जबकि निविदा के अनुसार 14.49 रूपए में कार्य आदेश जारी किया गया है जिसमे अनियमितता होने का संकेत हैं। सवाल उठ रहा है कि इतने कम में यदि संभव था तो अब तक सरकारी स्तर पर क्यों नहीं किया गया। यदि अब होगा तो कैसे हो जाएगा??

किसी रहेगी सिक्योरिटी और गारंटी

निविदा दाता से 25 लाख रुपये की बैंक गारंटी एवं 1,75,000 रुपये सिक्यूरिटी ली जाती है। त्रमासिक आवंटन 13000 क्विंटल गेहूं और चावल की बाजार मूल्य 3,25,00,000 करोड़ रुपये की होती है। एक तर्क दिया जा रहा है कि ठेकेदार अपने निजी गोदाम में यह माल भरेगा व यदि चोरी हो गया तो सरकार कैसे वसूल करेगी। संस्था में तो सरकारी कार्मिकों व गोदाम संस्था के स्वयं हो कर बीमित होते हैं। यहां पर जिम्मेदारी किसकी होगी। पूर्व में 3 माह पहले निविदा आमंत्रित की गई थी जिसमे में एक ही निविदा टेक्निकल में सफल रही थी, कार्य आदेश नहीं दे कर टेंडर प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया गया था। वर्तमान में भी 7 में से एक ही निविदा टेक्नीकल में सफल होने पर भी कार्य आदेश कैसे जारी हो गया। यह भी आरोप है कि वर्तमान फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी कमियां पूरी करने के लिए बुलाया गया, जबकि अन्य को यह अवसर सुलभ नहीं था। अब तक ऐसा नहीं होता था।

गोदाम को लेकर भी सरकारी दरियादिली

अभी सरकारी गोदामों पर ताले लगना तय है। उनका क्या होगा, यह पता नहीं है। समिति के पास आसपुर, सागवाड़ा व सीमलवाड़ा में गोदाम है। नई संस्थान ने प्राइवेट गोदाम हायर किए हैं। अब फर्म को अन्य जगहों पर गोदाम स्थापित करने का सुलभ अवसर टेण्डर की शर्तों के विपरीत दिया जा रहा है।

उदयपुर सिटी-कामाख्या और न्यूजलपाईगुडी-उदयपुर सिटी के मार्ग बदले, ये रहेगा नया शेड्यूल

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। तकनीकी कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित होगा व रेलसेवाएं मार्ग परिवर्तित रहेगी। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा कटिहार-मुकुरियां स्टेशनों के मध्य तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित निम्न रेलसेवाएं प्रभावित रहेगी:-

मार्ग परिवर्तित रेलसेवाएं (प्रारम्भिक स्टेशन से)

1. गाडी संख्या 19602, न्यूजलपाईगुडी-उदयपुर सिटी रेलसेवा जो दिनांक 03.02.25, 10.02.25, 17.02.25, 24.02.25 03.03.25, 10.03.25, 17.03.25, 24.03.25 व 31.03.25 को न्यूजलपाईगुडी से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग मुकुरियां -कुमदपुर-कटिहार होकर संचालित होगी।

2. डी संख्या 19615, उदयपुर सिटी कामाख्या रेलसेवा जो दिनांक 03.02.25, 10.02.25, 17.02.25, 24.02.25 03.03.25, 10.03.25, 17.03.25, 24.03.25 व 31.03.25 को उदयपुर सिटी से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा परिवर्तित मार्ग मुकुरियां -कुमदपुर-कटिहार होकर संचालित होगी।

संचालन समय में आंशिक परिवर्तन

रेलवे द्वारा गांधीधाम-जोधपुर रेलसेवा के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन एवं भगत की कोठी (जोधपुर)-पालनपुर व हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस रेलसेवा के मार्ग के कुछ स्टेशनों पर भी संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार:-

1. गाडी संख्या 22484, गांधीधाम-जोधपुर रेलसेवा दिनांक 06.02.25 से गांधीधाम से 23.20 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 23.15 बजे रवाना होकर 09.00 बजे के स्थान पर परिवर्तित समय 08.50 बजे जोधपुर पहुँचेगी।

2. गाडी संख्या 14893, भगत की कोठी -पालनपुर रेलसेवा जो दिनांक 06.02.25 से भगत की कोठी (जोधपुर) से प्रस्थान करेगी वह भीलडी स्टेशन पर 03.00 बजे आगमन व 03.10 बे प्रस्थान के स्थान पर परिवर्तित समय 02.50 बजे आगमन व 03.00 बजे प्रस्थान करेगी।

3. गाडी संख्या 19272, हरिद्वार-भावनगर टर्मिनस रेलसेवा जो दिनांक 05.02.25 से हरिद्वार से प्रस्थान करेगी उस रेलसेवा के मार्ग में सुरेन्द्रनगर गेट, लींबडी, बोटाद, ढोला, सिहोर गुजरात, भावनगर पारा व भावनगर टर्मिनस स्टेशनों पर संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है।

व्यक्ति अपनी कार्य शैली व व्यवहार से महान होता है - अधीक्षक डॉ आर एल सुमन, नर्सिंग अधीक्षक हसीना अहारी का सम्मान

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर। व्यक्ति अपनी कार्यशैली व व्यवहार से महान होता है। अपने कार्य क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण ईमानदारी के साथ करना चाहिए। अस्पताल में कई व्यक्ति लगन व उत्तम व्यवहार से बीमारों की सेवा करते हैं ये वाक्य एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ आर एल सुमन ने नर्सिंग अधीक्षक हसीना आहरी के सम्मान समारोह में कहा। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन उदयपुर शहर के जिला अध्यक्ष पवन कुमार दानाध्यक्ष व प्रवीण चरपोटा के नेतृत्व में नर्सिंग अधीक्षक हसीना आहरी का उत्कृष्ट नर्सिंग सेवाओं व व्यवहार के लिए पगड़ी पहनाकर, उपरणा शोल ओढ़ाकर, प्रसंशा पत्र , स्मृति चिन्ह व पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत व अभिनंदन किया । सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया ने बताया के मुख्य अतिथि नर्सिंग अधीक्षक गीता आहारी, ओमप्रकाश पालीवाल, शारदा गरासिया,ओम जोशी,हरिलता गंधर्व, ललीत कंसारा, श्री देवी, नूरानी मेहडा ,जीएनटीसी के प्रधानाचार्य डॉ जसवंत बैरवा थे । विशिष्ट अतिथि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत आमेटा, संरक्षक रमेश मीणा, सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया थे। सभी अतिथियों ने हसीना आहरी के कार्यों की खुब सरहाना की। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष परमार ने किया। कार्यक्रम लक्ष्मी नारायण चौहान, शर्मिला माली, डॉ विपिन मेहता, प्रमोद भाटी, चंद्र प्रकाश, जगदीश व दिनेश सिसोदिया, नारायण सिंह राठौड़ शकील अंसारी सुनीता सिंह, पुष्पा मालवारी, राजेंद्र जोशी, करण सिंह दक, राजूराम , चेतना लट्टा, दीपक मेघवाल सहित सैकड़ों सिनियर नर्सिंग आफिसर उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद सम्भागीय अध्यक्ष नरेश पूर्बिया ने दिया।

शातिर गैंग पकड़ी, गाड़ी को चुराते ही पुर्जा-पुर्जा बिखेर करे बेच देती, चार आरोपी गिरफ्तार

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. प्रतापगढ़। प्रतापगढ जिले के छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने गुरुवार को एक शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। यह गिरोह चोरी की गाड़ियों को खोलकर उनके पुर्जों को अलग-अलग बाजारों में बेचता था। इसके अलावा वाहनों का हुलिया बदलकर उन्हें अन्य राज्यों में भी बेच देते थे। पुलिस ने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के कुचडौद जंगल में दबिश देकर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और हाल ही में चुराई गई एक गाड़ी बरामद की। 27 जनवरी 2024 की रात एक टवेरा गाड़ी चोरी हो गई थी। पीड़ित योगेश कुमार जोशी ने अपनी गाड़ी विवेकानंद पार्क के पास खड़ी की थी। जब वे लौटे तो गाड़ी गायब थी। आसपास तलाश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर छोटीसादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक के नेतृत्व में विशेष जांच टीम बनाई गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जिसमें संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं।

जंगल में छिपाई थी चोरी की गाड़ी

पुलिस को सूचना मिली कि गाड़ी मंदसौर के कुचडौद जंगल में छिपाई गई है। पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर चोरी की गई गाड़ी बरामद की और मौके से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने गाड़ी चोरी करने की बात कबूल की। थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि आरोपी गाड़ी चोरी के बाद सबसे पहले उसकी पहचान मिटाने का काम करते थे। सबसे पहले वाहन की नंबर प्लेट बदल दी जाती थी। पार्ट्स अलग करना: गाड़ी के महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग कर दिया जाता था। स्क्रैप में तब्दील करना: कुछ पार्ट्स को स्क्रैप के रूप में बेच दिया जाता था। रंग और हुलिया बदलना: वाहनों का रंग और नंबर प्लेट बदलकर दूसरे राज्यों में बेचने की योजना बनाई जाती थी। आसिफ शाह, इमरोज शाह, इस्माइल शाह, बृजेश लोहार को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी मंदसौर जिले के निवासी हैं और चोरी, भंगार बेचने और वेल्डिंग जैसे काम में माहिर हैं। इस पूरे ऑपरेशन में छोटीसादड़ी थाना प्रभारी प्रवीण टांक के साथ उपनिरीक्षक नारायण लाल मैडा, हेड कांस्टेबल सुरेश, महेश, कांस्टेबल कमल, विनय प्रताप सिंह और अविनाश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रेलमगरा पुलिस ने 15 जगह दबिश देकर 6 वारंटी पकड़े

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. राजसमंद। वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत रेलमगरा थाना पुलिस द्वारा अलग अलग टीम बनाकर कुल 15 स्थानो पर दबिश देकर 06 स्थाई वारंटीयो को गिरफ्तार किया है। आदेशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेन्द्र पारीख व पुलिस उप अधीक्षक वृत नाथद्वारा के निर्देशन मे वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये गये रहे विशेष अभियान के तडत सोनाली शर्मा उ.नि. थानाधिकारी थाना रेलमगरा के नेतृत्व मे गठित अलग अलग कुल 03 टीमो द्वारा थाना सर्कल मे 15 स्थानो पर दबिश देकर कुल 06 स्थाई गिरफतारी वारंटीयो को गिरफतार किया जाकर न्यायालय मे पेश किया गया व 01 स्थाई गिरफतार वारंट का अन्य तरीके से निस्तारण किया गया।

डूंगरपुर में बड़ी कार्रवाई: कूलर की आड़ में तस्करी कर रहे दो आरोपी 69 कार्टन अवैध शराब के साथ गिरफ्तार

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर बिछीवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 69 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी गई है। तस्कर कूलर की आड़ में इस शराब को ले जा रहे थे।एसपी मोनिका सैन के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उदयपुर की ओर से एक कंटेनर अवैध शराब लेकर आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की। पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर को रोका और तलाशी ली। कंटेनर के भीतर कूलर के बीच छिपाकर रखे गए शराब के 69 कार्टन बरामद हुए। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर सुरेंद्र सिंह और उसके साथी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है ताकि तस्करी नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

तस्करी का तरीका

तस्करों ने कूलर की आड़ में शराब छिपाकर तस्करी करने की योजना बनाई थी ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई की जानी थी। इस कार्रवाई से पुलिस की सतर्कता और सक्रियता का परिचय मिलता है। विशेष अभियान के तहत शराब तस्करी के मामलों पर अंकुश लगाने की दिशा में यह एक बड़ी सफलता है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अन्य संभावित तस्करों और स्रोतों की तलाश भी जारी है।

अबके-बार : नई एक्साइज पॉलिसी मेंएयरपोर्ट पर खुलेंगे बार, प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज वाइन और एसेसरीज की बिक्री होगी

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. जयपुर। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली नई एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी है। इस नीति के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। पहली बार राजस्थान के एयरपोर्ट पर बार खोलने की अनुमति दी गई है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी तय करेगी कि बार का संचालन कब और कैसे होगा। यह फैसला राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि अन्य राज्यों के एयरपोर्ट्स पर बार संचालित होते हैं। एयरपोर्ट शॉप्स वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर जारी होंगी। जयपुर एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस फीस 20 लाख, अन्य शहरों के लिए 10 लाख निर्धारित की गई है। इन शॉप्स पर केवल प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज वाइन और एसेसरीज की बिक्री की जाएगी। खुलने और बंद होने के समय का निर्धारण एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी। 10 कमरों वाली होटलों को भी मिलेगा बार लाइसेंस नई पॉलिसी के तहत अब 10 कमरों वाली होटलों को भी बार लाइसेंस दिया जाएगा। पहले इसके लिए 20 कमरों की आवश्यकता होती थी। लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जो ऑटो अप्रूव होगी। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे जैसलमेर, माउंट आबू, पुष्कर, कुंभलगढ़ और सवाई माधोपुर में अब सीजनल लाइसेंस दिए जाएंगे। ये लाइसेंस उन जगहों के लिए होंगे जहां स्विस टेंट जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। पहले केवल वार्षिक लाइसेंस का प्रावधान था।

लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा

दुकान संचालकों को अगले चार साल तक लाइसेंस रिन्यू करवाने का विकल्प दिया गया है। उन्हें हर साल नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सालाना फीस में निर्धारित वृद्धि के साथ लाइसेंस रिन्यू किया जा सकेगा। इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना, शराब व्यापार को व्यवस्थित करना और पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना है। इसके साथ ही छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

राष्ट्रपति भवन में पहली बार गूंजेगी शहनाई, इस अधिकारी की सीआरपीएफ कमांडेंट बिटिया की है शादी

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. नेशनल डेस्क। राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा क्राउन परिसर में 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। पहली बार राष्ट्रपति भवन में किसी अधिकारी की शादी होगी। यह सम्मान मिला है शिवपुरी की बेटी पूनम गुप्ता को, जो वर्तमान में सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में राष्ट्रपति की सुरक्षा में पीएसओ के पद पर तैनात हैं। पूनम का विवाह जम्मू-कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार से होगा।

राष्ट्रपति का विशेष सम्मान

पूनम गुप्ता के अनुशासन, आचरण और कर्तव्यनिष्ठा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद प्रभावित हैं। जब राष्ट्रपति को पूनम की शादी के बारे में पता चला, तो उन्होंने स्वयं राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित मदर टेरेसा क्राउन परिसर में विवाह की अनुमति दी। समारोह में वर-वधू पक्ष के चुनिंदा मेहमान ही शामिल होंगे।

पूनम गुप्ता की उपलब्धियां

पूनम गुप्ता ने गणित में स्नातक और अंग्रेजी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से बीएड करने के बाद वे यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा 2018 में 81वीं रैंक प्राप्त कर सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनीं। वर्ष 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी का नेतृत्व किया था।

पारिवारिक पृष्ठभूमि

पूनम शिवपुरी के श्रीराम कॉलोनी की निवासी हैं। उनके पिता रघुवीर गुप्ता नवोदय विद्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पूनम की शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय, श्योपुर में हुई। शादी में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए विशेष औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, ताकि उन्हें राष्ट्रपति भवन में प्रवेश की अनुमति मिल सके। यह विवाह केवल एक पारिवारिक समारोह नहीं है, बल्कि देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है। पूनम गुप्ता जैसी महिला अधिकारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण से यह सिद्ध होता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही हैं।

विद्या संबल योजना में लगे सहायक आचार्यों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. हाईकोर्ट डेस्क। राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्या संबल योजना के तहत काम करने वाले व्याख्याता सहित, असिस्टेंट प्रोफेसर को बड़ी राहत दी हैं। कोर्ट की ओर से बताया गया है कि 'वर्तमान सत्र में अभी काम कर रहे लोगों को ही प्राथमिकता देते हुए रखा जाए, नए विज्ञापन में उन्हें प्राथमिकता दी जाए, साथ ही उनके स्थान पर अन्य किसी को नहीं रखा जाए', जस्टिस अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने यह आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता डॉ. प्रीति भट्ट व अन्य की याचिका पर दिए आदेश, याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि 'याचिकाकर्ता पूर्व से विद्या संबल योजना में पढ़ा रहे हैं। अब दौसा राजकीय कॉलेज की ओर से नए सिरे से विद्या संबल योजना के अंतर्गत व्याख्याता लिए जा रहे है। उनके स्थान पर अन्य किसी को लेना विधि विरुद्ध है, उन्हें हटाकर अन्य को नहीं लिया जा सकता हैं।

PM किसान योजना के नाम पर ग्रामीण को बनाया शिकार APK फाइल भेजकर हैक किया मोबाइल, 2 लाख रुपए निकाले

24 न्यूज अपडेट

प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम पर किसानों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर ग्रामीण के खेड़ापा थाना क्षेत्र में सामने आया है। ठगों ने किसान को किसान निधि के नाम पर मोबाइल पर एक एपीके फाइल भेजी। जिस पर क्लिक करते ही किसान का मोबाइल हैक हो गया। उसके खाते से 2 लाख से ज्यादा की राशि निकाल ली गई। हालांकि समय रहते साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाने की वजह से ठगी की राशि होल्ड करवाई गई।

ग्रामीण एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया- परिवादी महादेव सिंह निवासी चिंदिया को ठगों ने पीएम किसान एपीके फाइल लिंक भेजी। जिस पर क्लिक करने पर उसका मोबाइल ठगों ने हैक कर दिया और उसके बैंक खाते से 2 लाख 4 हजार 100 रुपए की राशि निकाल ली गई। इसका पता चलने पर परिवादी की ओर से 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई गई। जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर सेल की ओर से 1 लाख 83 हजार 369 रुपए होल्ड करवाए गए। वहीं पुलिस थाना खेड़ापा की ओर से कोर्ट से रिफंड ऑर्डर करवा कर 1 लाख 70000 रुपए की राशि परिवादी के बैंक खाते में वापस रिफंड करवाने में सफलता हासिल की है। इस पूरी प्रक्रिया में साइबर सेल के कॉन्स्टेबल पुखराज, दयाल सिंह, खेड़ापा थाने के कॉन्स्टेबल प्रकाश गोस्वामी शामिल रहे।

हेड कॉन्स्टेबल को धक्का देकर थाने से भागा बदमाश

24 न्यूज अपडेट

जयपुर के संजय सर्किल पुलिस स्टेशन से एक क्रिमिनल के भागने का मामला सामने आया है। टॉयलेट के लिए हवालात से बाहर निकलने पर पुलिसकर्मी को धक्का देकर भाग गया। पुलिस टीम की पकड़ से बचने के लिए दीवार से कूदने पर उसका पैर टूट गया। पुलिस टीम ने थाने से भागे क्रिमिनल को पकड़ कांवटिया हॉस्पिटल में इलाज कराया, उसके के बाद उसे अरेस्ट कर लिया है। SHO (संजय सर्किल) हरिओम सिंह ने बताया- तीन दिन पहले संजय सर्किल थाना पुलिस ने डकैती की प्लानिंग करते छह बदमाशों को अरेस्ट किया था। गिरफ्तार बदमाशों में मुमताज अली (21) निवासी कटिहार बिहार हाल पेंटर कॉलोनी शास्त्री नगर भी था। बुधवार सुबह करीब 4:45 बजे टॉयलेट के लिए हवालात से मुमताज अली को बाहर निकाला गया। इस दौरान हेड कॉन्स्टेबल को मुमताज अली धक्का देकर थाने से बाहर भाग गया। मुलजिम के भागने का पता चलने पर पुलिस के जवान उसको पकड़ने पीछे भागे। अंधेरे का फायदा उठाकर मुमताज अली भाग निकला।

पुलिस टीम ने थाने से भागे क्रिमिनल मुमताज अली के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस टीम को रात करीब 10:30 बजे खेतड़ी हाउस पर दिखा। पुलिस को देखकर मुमताज ने दीवार कूदकर भागने का प्रयास किया। दीवार से कूदने पर उसका पैर टूटने से घायल हो गया। पुलिस ने चोटिल हुए मुमताज को पकड़ कांवटिया हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। इलाज के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। संजय सर्किल थाना पुलिस ने पुलिस स्टेशन से भागने के चलते आरोपी मुमताज के खिलाफ अलग से एक और FIR दर्ज की है।

नॉन RAS से IAS में प्रमोशन मामला,याचिका SC में खारिज

24 न्यूज अपडेट

राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद (आरएएस एसोसिएशन) की याचिका को खारिज कर दिया है। एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के 5 दिसम्बर 2024 के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने नॉन आरएएस से आईएएस में प्रमोशन को सही माना था। वहीं, व्यक्तिगत हितों के चलते कोर्ट का समय बर्बाद करने पर एसोसिएशन पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि को कम करते हुए उसे 2 लाख कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा- राज्य सरकार ने नॉन आरएएस अधिकारियों को पदोन्नति देने की प्रक्रिया में कोई नियम नहीं तोड़ा है।

याचिका में कहा गया था - हाईकोर्ट ने तथ्यों को नजर अंदाज किया

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की ओर से याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थितियों होने पर ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत कर सकती है। उसमें भी स्टेट सिविल सर्विसेज के 33.33 प्रतिशत कोटे का 15 प्रतिशत अन्य सेवाओं से ले सकती है। सरकार तो हर साल पर्याप्त आरएएस ऑफिसर होने के बाद भी अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिश भेज रही है। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (रिक्रूटमेंट) रूल्स 1954 के तहत राज्य सरकार को यह पावर है कि वह नॉन सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत करने की सिफारिश यूपीएससी को भेज सकती है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य में विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हों। वहीं, जिस अधिकारी का इस पद के लिए चयन किया जा रहा है, उसमें कोई विशेष योग्यता हो। जो मौजूदा सिविल सर्विसेज के किसी भी अधिकारी में नहीं हो। केवल उसी सूरत में नॉन सिविल सर्विसेज के अधिकारी को आईएएस में पदोन्नत किया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजर अंदाज करके फैसला सुनाया हैं।

भोपाल में फूड कंपनी डायरेक्टर की आत्महत्या की कोशिश: केंद्रीय मंत्री समेत 6 पर गंभीर आरोप

24 न्यूज अपडेट

24 न्यूज अपडेट. नेशनल डेस्क। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स की निदेशक पायल मोदी ने चूहे मारने की दवा खाकर आत्महत्या की कोशिश की। उन्हें भोपाल के बंसल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे की है। पायल मोदी ने कथित रूप से एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और 5 अन्य लोगों को जिम्मेदार ठहराया है।

सुसाइड नोट के मुख्य आरोप: चिराग पासवान और उनके रिश्तेदारों पर राजनीतिक पावर का दुरुपयोग करने का आरोप। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स पर सीजीएसटी व ईडी के छापे डलवाने का आरोप लगाया। पायल और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिलने का आरोप। सुसाइड नोट पुलिस ने जब्त नहीं किया है, लेकिन जांच जारी है। पायल मोदी के पति किशन मोदी ने सुसाइड नोट की पुष्टि की है। पायल मोदी की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, और सभी आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा रहा है।

सुसाइड नोट का भावुक हिस्सा:"मेरे तीन छोटे बच्चे हैं, इसके बावजूद भी मुझे यह कदम उठाना पड़ रहा है। छापों के चलते मेरे पति, जो हार्ट पेशेंट हैं, की तबीयत बिगड़ गई है। हमने हर संभव जगह न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई।"

पायलट बोले- महाकुंभ के नाम पर नहीं हो राजनीति कहा- केंद्र सरकार राजस्थान को दे विशेष राज्य का दर्जा

24 न्यूज अपडेट

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होटल क्लार्क आमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर नाराजगी जाहिर की। वहीं केंद्र सरकार से बजट में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की।

सचिन पायलट ने कहा, मैं हर साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आता हूं। मुझे लगता है कि हम होस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां सभी खुले मन से बात करते हैं। अलग-अलग विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान होता है। भले ही सहमति न बने, लेकिन सुनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। उस पर जेएलएफ में चर्चा होती है। जिसमें जयपुर वासियों को दिल खोलकर सबका स्वागत करने का मौका मिलता है।

दुनियाभर में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इसका जन्म जयपुर में हुआ है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। इसलिए सबको सहयोग कर इसे और बड़ा बनाना चाहिए। क्योंकि ऐसे आयोजनों से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बहुत कम राज्य होंगे, जिनके पास राजस्थान की तरह रिच आर्ट, कल्चर और हेरिटेज है। उसे बचाने की, बढ़ाने की जरूरत है। ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकें।

इस दौरान महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज जाने के सवाल पर जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति की अपनी निजी आस्था है। उसका दिखावा या उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हर व्यक्ति को अपने मजहब और धर्म की पालना करने की पूरी छूट है।

सचिन पायलट ने कहा कि कल केंद्र सरकार बजट जारी करने जा रही है, लेकिन पिछले कई सालों में यह देखने को मिला है कि बजट में राजस्थान की अनदेखी की जाती है। जबकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग यहां रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान को लेकर गलत नजरिया अपना रखा है। राजस्थान में कोई नई राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो रही है। नई रेल लाइन से लेकर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तक नहीं दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यहां तक की राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया जा रहा है। पिछले बजट में तो वित्त मंत्री ने राजस्थान का नाम तक नहीं लिया था। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की भाजपा सरकार केंद्र सरकार पर दबाव डालकर राजस्थान को फायदा दिलाने की कोशिश करेगी। ताकि राजस्थान में निवेश और रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोतरी हो।

सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में भी विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए कामकाज का लेखा-जोखा सदन में रखेंगे। जिस तरह से बीजेपी सरकार बनने के बाद स्कूलों को बंद किया गया है। जिलों को खत्म किया गया है। उसका जवाब सदन के पटल पर मांगा जाएगा।

मोटर गैराज विभाग का सीएमएचओ को फरमान-पेट्रोल-डीजल के बकाया 1 करोड़ जमा करवाओ नहीं तो सप्लाई हो जाएगी बंद!

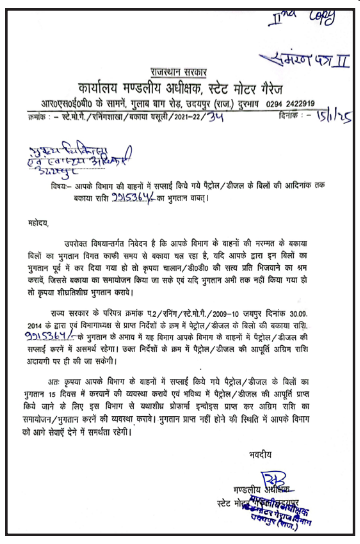
IInd Copy
स्मरण पत्र II
राजस्थान सरकार
कार्यालय मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैरेज
आर०एस०ई०बी० के सामने, गुलाब बाग रोड, उदयपुर (राज.) दूरभाष 0294 2422919
क्रमांक :- स्टे.मो.गै./रनिंगशाखा/बकाया वसूली/2021-22/34 दिनांक :- 15/1/25

विषय:- आपके विभाग की वाहनों में सप्लाई किये गये पैट्रोल/डीजल के बिलों की आदिनांक तक बकाया राशि 9915364/- का भुगतान बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके विभाग के वाहनों की मरम्मत के बकाया बिलों का भुगतान विगत काफी समय से बकाया चल रहा है, यदि आपके द्वारा इन बिलों का भुगतान पूर्व में कर दिया गया हो तो कृपया चालान/डी०डी० की सत्य प्रति भिजवाने का श्रम करावें, जिससे बकाया का समायोजन किया जा सके एवं यदि भुगतान अभी तक नहीं किया गया हो तो कृपया शीघ्रतिशीघ्र भुगतान करावें।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2/रनिंग/स्टे.मो.गै./2009-10 जयपुर दिनांक 30.09.2014 के द्वारा एवं विभागाध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पैट्रोल/डीजल के बिलो की बकाया राशि 9915364/- के भुगतान के अभाव में यह विभाग आपके विभाग के वाहनों में पैट्रोल/डीजल की सप्लाई करने में असमर्थ रहेगा। उक्त निर्देशों के क्रम में पैट्रोल/डीजल की आपूर्ति अग्रिम राशि अदायगी पर ही की जा सकेगी।

अतः कृपया आपके विभाग के वाहनों में सप्लाई किये गये पैट्रोल/डीजल के बिलों का भुगतान 15 दिवस में करवाने की व्यवस्था करावें एवं भविष्य में पैट्रोल/डीजल की आपूर्ति प्राप्त किये जाने के लिए इस विभाग से यथाशीघ्र प्रोफार्मा इन्वोइस प्राप्त कर अग्रिम राशि का समायोजन/भुगतान करने की व्यवस्था करावें। भुगतान प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके विभाग को आगे सेवाएँ देने में समर्थता रहेगी।

भवदीय
मण्डलीय अधीक्षक
स्टेट मोटर गैरेज विभाग
उदयपुर (राज.)

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. उदयपुर। डिजिटल जमाने में सरकारी काम किस अंदाज में होते हैं इसकी एक बानगी देखिये। उदयपुर में इस महीने की 15 तारीख को स्टेट मोटर गैराज कार्यालय से एक पत्र सीएमएचओ के दफ्तर को भेजा गया। लेकिन 16 दिन बाद भी यह पत्र सीएमएचओ को मिला ही नहीं। जमा नहीं करवाया तो विभाग की गाड़ियों का चक्का जाम हो जाएगा। तेल नहीं दिया जाएगा और आगे के लिए भी तेल चाहिए तो पहले रोकड़ा जमा होगा, उसके बाद तेल या ईंधन दिया जाएगा। यह कोई छोटा-मोटा लेटर नहीं, बल्कि पेट्रोल डीजल के सीएमएचओ के विभाग में बकाया 99 लाख की तुरंत वसूली का लेटर है। दोनों दफ्तरों में इतना कम फासला है कि यदि सुस्त से सुस्त कर्मचारी को भी इस काम में लगा दिया जाए तो वह भी एक घंटे में पूरा करके लौट सकता है। लेकिन यहां लगभग 1 करोड़ की वसूली की चिट्ठी 16 दिन बाद भी ना जाने कौनसी गति से चल रही है कि अब तक सीएमएचओ विभाग में नहीं पहुंची है। मोटर गैराज वाले कह रहे हैं कि हमने तो चिट्ठी भेज दी, सीएमएचओ कह रही हैं कि हमें तो चिट्ठी मिली ही नहीं। आखिर क्या है ये उलझन। किसी एक विभाग का पेट्रोल-डीजल का क्या लगभग 1 करोड़ रूपया बकाया भी हो सकता है क्या? इतना पेट्रोल-डीजल कब, किसने खर्च किया। आदि जानने के लिए हमने अफसरों से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में जो चिट्ठी जारी हुई है उसके आधार पर ही कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।

यह जारी हुआ पत्र

राजस्थान सरकार के कार्यालय मण्डलीय अधीक्षक, स्टेट मोटर गैरेज की ओर से क्रमांक स्टे. मो.गै./ रनिंग शाखा / बकाया वसूली/2021-22/34 नामक चिट्ठी को 15 जनवरी, 2025 को जारी किया गया। इसमें सीएमएचओ को संबोधित करते हुए लिखा गया कि आपके विभाग की वाहनों में सप्लाई किये गए पेट्रोल / डीजल के बिलों की आदिनांक तक बकाया राशि 99 लाख 15 हजार 364 का भुगतान करवाया जाए। मण्डलीय अधीक्षक ने लिखा कि सीएमएचओ के विभाग के वाहनों की मरम्मत के बकाया बिलों का भुगतान विगत काफी समय से बकाया चल रहा है। यदि आपके द्वारा इन बिलों का भुगतान पूर्व में कर दिया गया हो तो कृपया चालान / डी०डी० की सत्य प्रति भिजवाने का श्रम करावें, जिससे बकाया का समायोजन किया जा सके एवं यदि भुगतान अभी तक नहीं किया गया हो तो कृपया शीघ्रतिशीघ्र भुगतान कराएं।

नहीं तो बंद कर देंगे सेवाएं, बे-कार हो जाएंगे वाहन

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.2/ रनिंग/स्टे.मो.गै. /2009-10 जयपुर दिनांक 30.09. 2014 के द्वारा एवं विभागाध्यक्ष से प्राप्त निर्देशों के क्रम में पेट्रोल/डीजल के बिलो की बकाया राशि 9915364/-के भुगतान के अभाव में यह विभाग आपके विभाग के वाहनों में पैट्रोल / डीजल की सप्लाई करनें में असमर्थ रहेगा। उक्त निर्देशों के क्रम में पैट्रोल/डीजल की आपूर्ति अग्रिम राशि अदायगी पर ही की जा सकेगी। अतः कृपया आपके विभाग के वाहनों में सप्लाई किये गये पैट्रोल/डीजल के बिलों का भुगतान 15 दिवस में करवाने की व्यवस्था करावें एवं भविष्य में पैट्रोल / डीजल की आपूर्ति प्राप्त किये जाने के लिए इस विभाग से यथाशीघ्र प्रोफार्मा प्राप्त कर अग्रिम राशि का समायोजन/भुगतान करनें की व्यवस्था करवाएं भुगतान प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आपके विभाग को आगे सेवाएं देने में समर्थता रहेगी।

इतना उधार कैसे कर लिया? यहां तो 100 रूपए का बिल जमा नहीं होने पर कट जाता है कनेक्शन

यह अजीब बात है कि एक सरकारी विभाग दूसरे का पैसा नहीं दे रहा हैं। इस मामले में पत्र में यह नहीं बताया गया कि बकाया की अवधि कितने की है? लेकिन केवल सीएमएचओ के मातहत आने वाले विभागों में पेट्रोल डीजल का 1 करोड़ का कर्जा आखिर कैसे चढ़ गया यह बहुत बड़ा सवाल है। यह पैसा नहीं दिया तो आगे से ईंधन नहीं दिया जाएगा, यह चेतावनी भी है। चिट्ठी का जवाब 15 दिन में देना है, लेकिन 15 दिन बाद भी चिट्ठी सीएमएचओ को मिली ही नहीं है, यह भी अजीब बात है। एक और खास बात ये है कि यदि जनता 100 रूपए का बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करवाती है तो पूरा प्रशासनिक लवाजमा उसके साथ अपराधी जैसा बर्ताव करते हुए कनेक्शन काटने आ जाता है। सार्वजनिक बदनामी करता है। यहां पर तो 1 करोड़ का ईंधन का पैसा नहीं देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

खेतों पर मचान बना कर ऑनलाइन फ्रॉड करते हुए देशभर के लोगों से लूट लिए 1 करोड़

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. डूंगरपुर। डूंगरपुर में एक अनोखे तरीके से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने खेतों में पेड़ पर मचान बनाकर ठगी का संचालन कर रहे आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को ठग रहा था। अब तक एक करोड से अधिक लूट चुके हैं। इन अपराधियों के खिलाफ देशभर में साइबर ठगी की कुल 55 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने इनके पास से 16 मोबाइल फोन और 22 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। यह कार्रवाई ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत साइबर थाना और साबला थाना पुलिस द्वारा की गई। पुलिस को इस गिरोह की जानकारी मुखबिर से मिली थी, जिसने बताया कि कुछ लोग पेड़ों पर मचान बनाकर वहां से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। जब अधिकारियों ने पेड़ों पर बने मचानों की जांच की, तो वहां बैठे ठगों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट की जांच करने पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने के पुख्ता प्रमाण मिले। इस गिरोह के सदस्य पिंडावल, बोडीगामा, पालोदा और वजेपुरा गांवों के रहने वाले हैं। गिरफ्तार आरोपियों में पिंडावल निवासी दलजी पुत्र पाटीदार, जितेंद्र पुत्र परती पाटीदार, बोडीगामा निवासी डायालाल पुत्र ताजेंग पाटीदार, कमलेश पुत्र नारायण पाटीदार, परीक्षित पुत्र भगु पाटीदार, हितेश पुत्र बंशीलाल पाटीदार, पालोदा निवासी राजेश पुत्र गौतम पाटीदार और वजेपुरा निवासी राहुल पुत्र दिनेश चंद्र डामोर शामिल हैं। इन अपराधियों ने अब तक देशभर में एक करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। विभिन्न राज्यों में इनके खिलाफ साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायतें दर्ज की गई थीं। पुलिस अब आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि उनके अन्य साथियों और ठगी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। इस मामले ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरों को उजागर किया है और यह दिखाता है कि अपराधी पुलिस से बचने के लिए लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं।

क्रेटा कार से 32 किलो अवैध डोडाचूरा जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. चित्तौड़गढ़। मंडफिया थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान एक क्रेटा कार से 32 किलो 800 ग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त कर बाड़मेर जिले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन एवं डीएसपी भदेसर अनिल शर्मा के पर्यवेक्षण मे थानाधिकारी मण्डफिया गोकुल लाल डांगी उ.नि व पुलिस जाप्ता एएसआई ब्रजलाल, कानि. महेन्द्र, खुबचन्द, संदीप कुमार, दुर्गाशंकर व नारायण लाल द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त के दोरान बाड़मेर जिले के वांकलसर मंगले की बेरी थाना नगर आर.जी.टी. निवासी 20 वर्षीय शंभूराम पुत्र धर्माराम जाट के कब्जे से 32 किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफिम डोडाचूरा को परिवहन करते हुये गिरफतार कर उक्त मादक पदार्थ अफिम डोडाचूरा को जब्त किया गया व परिवहन में प्रयुक्त वाहन केटा कार को जब्त किया गया। आरोपी से अवैध डोडाचुरा की खरीद फरोख्त के सम्बंध मे पुछताछ जारी है।

सांसद रावत ने दिशा के तहत बंद योजनाओं को हटाने व नई योजनाओं को जोडने केंद्रीय मंत्री चौहान को लिखा पत्र

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर, 31 जनवरी। सांसद मन्नालाल रावत ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अन्तर्गत योजनाओं व कार्यक्रमों की सूची को अपडेट करने का आग्रह किया है। असल में समिति के तहत चल रही कई योजनाएं वर्तमान में बंद हो चुकी है और कई योजनाएं ऐसी हैं जो चल रही है, लेकिन शामिल नहीं है। सांसद श्री रावत ने केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) के अन्तर्गत विभिन्न मंत्रालयों व विभागों की कुल 67 योजनाओं को दिनांक 1 दिसंबर 2023 के संशोधित दिशा निर्देश द्वारा सम्मिलित किया गया है। जबकि 15 जनवरी 2025 को आयोजित जिला सलूम्बर की दिशा समिति की जिला स्तरीय बैठक में उनकी जानकारी में लाया गया कि पूर्व में जारी दिशा निर्देश में सम्मिलित कुछ योजनाएं वर्तमान में संचालित नहीं है एवं कुछ योजनाएं जो वर्तमान में संचालित हैं परन्तु दिशा समिति के दिशा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में जो योजनाएं सूची में शामिल है, लेकिन संचालित नहीं हैं उनमें ग्रामीण विकास विभाग की श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएसआरएम) व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएम जीडीआईएसएच) है। वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं, लेकिन समिति में शामिल नहीं है उनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की पीए किसान, पीए कुसुम, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पीपीआर वेक्सिनेशन, शिक्षा मंत्रालय की पीएम श्री विद्यालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पीएम वाणी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पीएम श्रम योगी मानधन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पीएम सूर्य घर योजना, मत्स्य विभाग की मत्स्य सम्पदा योजना, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की पीएम विश्वकर्मा योजना, बैंक एवं वित्त मंत्रालय की प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टेंड अप इण्डिया, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फार्मलाईजेशन ऑफ माईको फुड प्रोसेसिंग एन्टरप्राईजेज तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के साथ ही जनजाति कार्य मंत्रालय की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना शामिल है। सांसद श्री रावत ने पत्र में आग्रह किया है कि दिशा समिति में योजनाओं को अपडेट करवाए ताकि जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसाः नवविवाहित युवक की मौत, साथी घायल

24 न्यूज़ अपडेट

24 न्यूज अपडेट. प्रतापगढ़। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-56 (एनएच-56) पर छायण गांव के पास हुई। पटेलिया से छोटी बंबोरी लौट रहे दो दोस्तों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 26 वर्षीय विजय मीणा पुत्र श्यामलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी अनिल मीणा पुत्र कालू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने विजय को मृत घोषित कर दिया। अनिल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक विजय की छह महीने पहले ही शादी हुई थी। उनका परिवार मजदूरी करके जीविका चलाता है। विजय के माता-पिता और दो बहनें हैं। विजय ने केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और मेहनत-मजदूरी करके परिवार का सहारा बन रहा था। थाना अधिकारी छबिलाल मीणा ने बताया कि दुर्घटना में कार और बाइक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल अनिल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर कार्रवाई जारी है।

हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू:

हादसे के वक्त दोनों दोस्त विजय की बड़ी बहन से मिलकर घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार वाहन का टक्कर मारना दुर्घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप चुकी है। इस हादसे ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है। तेज रफ्तार वाहन चलाना और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण अक्सर ऐसे हादसे होते हैं।

कानोता कैंप में होगा जयपुर बर्ड फेस्टिवल

ग्रीन पीपल सोसाइटी आयोजित कर रही है परिंदों का मेला

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर, 31 जनवरी। राजस्थान में हो रहे बर्ड फेस्टिवल की श्रृंखला में पहली बार ग्रीन पीपल सोसाइटी उदयपुर (जयपुर चैप्टर) द्वारा शनिवार, 1 फरवरी को जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस बर्ड फेस्टिवल में विद्यार्थी परिंदों की रंगीन दुनिया से रूबरू होंगे। इसके सफल आयोजन के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं। प्रदेशभर के पक्षी प्रेमी और विशेषज्ञ कानोता पहुंच चुके हैं।

फेस्टिवल संयोजक रिटायर्ड आईएएस विक्रम सिंह ने बताया कि जामडोली के पास कानोता कैंप रिसोर्ट में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में लगभग 500 विद्यार्थियों, शिक्षकों व बर्ड प्रेमियों के लिए विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जाएगी। सिंह ने बताया कि वन विभाग, पर्यटन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, रीको तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया के सहयोग से आयोजित होने वाले इस बर्ड फेस्टिवल में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत संभागियों व विद्यार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा और विद्यार्थियों को विद्यार्थी किट, अल्पाहार, पक्षी पहचान पुस्तिका, कार्डबोर्ड नेस्ट, डीआईवाय किट व टोपी का वितरण किया जाएगा। इसके बाद पक्षी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में स्पॉटिंग स्कोप एवं दूरबीन के माध्यम से बर्ड वॉचिंग करवाई जाएगी। साथ ही पेंटिंग व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पक्षी चित्रों पर डाक टिकटों की प्रदर्शनी, पक्षियों पर समूह चर्चा, आर्द्रभूमियों पर सम्मेलन-कार्यशाला आदि का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा प्रशिक्षक, स्कूल शिक्षक, गैर सरकारी संगठनों को सशक्त बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण हेतु एक विशेष कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी जिसमें मानव संसाधन के विभिन्न पहलुओं पर बेंगलुरु स्थित विशेष संगठन अली बर्ड द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

बर्ड फेस्टिवल में गुजरात से एमके रणजीत सिंह, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के चीफ रवि सिंह, असद रहमानी, ग्रीन पीपल सोसायटी के अध्यक्ष व एनटीसीए मेंबर राहुल भटनागर सहित देश—प्रदेश के पर्यावरण व पक्षी विशेषज्ञों द्वारा भाग लिया जाएगा।

वेटलैंड्स पर कार्यशाला व फील्ड विजिट का रहेगा आकर्षण :

विक्रम सिंह ने बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 1 फरवरी को वेटलैंड्स पर कार्यशाला-सम्मेलन का आयोजन होगा जिसमें वन एवं पर्यावरण, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल संसाधन, पर्यटन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर निगम और बैंकों आदि के वरिष्ठ अधिकारी, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के प्रतिनिधि, चयनित गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञ और भाग लेंगे। चिकित्सकों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से विचार-विमर्श में भाग लेने की उम्मीद है। वहीं प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों के लिए टीओटी-कार्यशाला का आयोजन होगा जिसमें पक्षियों और उनके आवास आदि के विभिन्न पहलुओं पर बेंगलुरु स्थित एक विशेषज्ञ संगठन 'अर्ली बर्ड' द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर लगभग 25-30 प्रतिनिधियों को फील्ड विजिट करवाई जाएगी। इसके तहत जयपुर के पास बरखेड़ा-चंदलाई-मुहाना, सांभर साल्ट लेक, केएनपी भरतपुर ताल छापर चूरू आदि स्थलों का भ्रमण कराना प्रस्तावित है।

"राजस्थान दिव्यांग सामान्य संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान" ब्राह्मकुमारीज मे प्रारम्भ

उदयपुर ब्रह्माकुमारी मोती मगरी स्कीम सेवा केंद्र द्वारा दिव्यंग सेवा अभियान का उद्घाटन किया गया

24 न्यूज़ अपडेट

उदयपुर 31 जनवरी प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वाविध्यालय उदयपुर मोती मंगरी सेवा केंद्र मे आज राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा प्रकल्प "राजस्थान दिव्यांग सामान्य संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान" का शुभारम्भ हुआ। उदयपुर संचालिका ब्रह्माकुमारी रीता बहन ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को सामान्य व्यक्ति के साथ समानता संरक्षण के लिए सभी नागरिकों की जिम्मेदारी सिखाना एवं दिव्यांगों को स्वास्थ्य शक्ति करण द्वारा मजबूत बनाना ताकि दिव्यांग अपनी संभाल एवं सुरक्षा स्वयं कर सके। साथ ही बुद्धि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, एवं मंदबुद्धि दिव्यांग भाई बहनों को एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग-अलग वैल्यू गेम्स खिलाए जाएंगे जिससे को अपनी सुरक्षा करने की दक्षता हांसिल कर सके। यह अभियान राजस्थान के विभिन्न जिलों में जाकर दिव्यांग लोगों की सेवा करेगा। मीडिया समन्वयक प्रोफेसर विमल शर्मा ने बताया कि समारोह मे आइ सी आइ सी आइ बैंक मैनेजर मिथिलेश श्रीवास्तव, इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष रेखा भाणावत, माउंट आबू से पधारे ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमारीज सूर्यमणि भाई जी, करनाल सूर्य प्रकाश जी एवं यात्रा में जाने वाले यात्री भाई बहने उपस्थित रहे।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।